प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

बजट

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में दो लाख करोड रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष की अवधि में चार करोड से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढाने की पांच योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार रुपये से बढाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कम्पनियों पर कॉरपोरेट कर दर चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की। निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले दो वर्ष में प्रमाणन और ब्रैंडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में एक करोड किसानों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार, जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। बजट में महिला नीत विकास को बढावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर तीन लाख करोड रुपये से अधिक का आबंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड रुपये का निवेश करेगी।

प्रधानमंत्री–बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024–2025 विकसित भारत के लिए है जो चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है।

मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि केन्द्रीय बजट में हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल में हुई आपदा में पुर्नवास के लिए सहायता की बात की गई है। लेकिन इसमें भी भेदभाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत और पुर्नवास के लिए केन्द्रीय बजट में हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखण्ड का जिक्र किया गया है और हिमाचल को बजट में अलग से कुछ भी नहीं मिला है।

नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा है कि केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बजट को दूरदर्शी, सर्व–स्पर्शी व सर्व–समावेशी होने के साथ गरीब, महिला, युवा व अन्नदाता वर्ग के कल्याण को चरितार्थ करने और उद्योग व अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने वाला बताया है। नड्डा ने विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया

अनुराग ठाकुर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि बजट में केन्द्र से मिली सहायता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण व राहत कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। एक बयान में उन्होंने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल में क्षतिपूर्ति के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष आपदा के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए एक हजार 7 सौ 82 करोड़ रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की।

जल जीवन मिशन

केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देशभर में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया जो एक बडी उपलब्धि है। मिशन के तहत यह काम तेजी से किया गया जिससे 2019 से लेकर 2024 के बीच पांच साल के अंदर 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कि जल जीवन मिशन के जरिए न केवल लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया।